'Statistical Statements Relating to the Cooperative Movement in India' which is an annually published document available in the Parliament Library.

The cooperative credit institutions themselves and the State Governments who are incharge of the subject of 'Cooperations' are primarily responsible for taking steps to collect the overdues. Steps like coercive action against wilful defaulters, rehabilitation of non-wilful defaulters by way of extension of the repayment period, strengthening the recovery machinery and action against indifferent and inefficient committees of management of the credit institutions, are being taken to reduce overdues.

The Reserve Bank of India and the Government of India have also been advising the State Governments from time to time on the need for taking effective steps for recovery. Recently, Union Minister for Agriculture and Irrigation has addressed all Chief Ministers for gearing up the recovery machinery in their States.

Inquiry into Bio-Chemistry Department of I.A.R.I.

129. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the employees of Indian Agricultural Research Institute have urged the Government to institute an inquiry into working specially of its Bio-Chemistry Department; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) Two Scientists of the Bio-Chemistry Division of the Indian Agricultural Research Institute (IARI) have represented that the Ministry of Home Affairs may be requested to constitute an independent judicial body to probe into the alleged grave injustice done to them during the last one decade.

(b) The Scientists concerned had earlier filed writ petitions regarding their grievances in the Hon. Delhi High Court which were dismissed. The Director, IARI has constituted a committee of senior officers to look into their grievances. It is for these scientists to submit their grievances to this committee.

सरकारी आवास का कब्जा लेने में तत्सम्बन्धी नियमों में ढील देना

130. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री सरकारी आवास का कब्जा लेने संबंधी नियमों में ढील देने के बारे में 12 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3565 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित अधिकारों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने फ्लैट का कब्जा नहीं दिया था क्योंकि उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था ;

(ख) क्या तत्कालीन सम्पदा निदेशक ने स्वयं उस स्थल का दौरा किया था और फ्लैट को देखा था और उस फ्लैट का कब्जा देने की तारीख आगे बढ़ा दी थी ; और

(ग) क्या उक्त अधिकारों को आपात स्थिति के दौरान परेशान किया गया था और जिस फ्लैट के बदले में उसे यह फ्लैट दिया गया था, उसके लिये उससे अब भी मार्केट किराया वसूल किया जा रहा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं । जब फ्लैट का आवंटन किया गया था तो उस समय इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था । अधिकारी ने आवंटन के विरुद्ध इस आधार पर अभ्यावेदन दिया था कि वह फ्लैट धोबी घाटों से घिरा हुआ है ।

(ख) जी, हां । अधिकारी के अनुरोध पर दखल की तारीख बढ़ा दी गई थी ।

(ग) अधिकारी को तंग नहीं किया गया । नियमों के अनुसार नार्थ एवेन्यू के

फ्लैट नं० 111 के अनधिकृत दखल की अवधि के लिये उनसे मार्केट दर पर लाइसेंस फीस वसूल की जा रही है । यह राशि 100 रुपए की मासिक किस्तों में वसूल की जा रही है ।

राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा परिषद् का भंग किया जाना

131. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा परिषद् को भंग कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस परिषद् के कर्मचारियों को खपाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ;

(ग) इस परिषद् के भंग होने के फलस्वरूप श्रेणीवार कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं तथा उनका सेवाकाल कितना है ; और

(घ) उनमें से कितने लोगों को नौकरियां उपलब्ध करा दी गई हैं तथा क्या उन्हें उनकी वरिष्ठता के अनुसार खपाया जा रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द): (क) जी, हां ।

(ख) स्कूल स्तर पर परिषद् के कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा और विश्वविद्यालय स्तर पर वि० अ० आ० द्वारा निष्पादित किये जा सकते हैं । इस कदम से प्रभावित 16 कर्मचारियों में से 10 को अन्य स्वायत्त तथा अर्ध-सरकारी संगठनों में वैकल्पिक रोजगार प्राप्त करवा दिए गये हैं और बाकी 6 कर्मचारियों के लिये रोजगार ढूंढने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में दे दी गई है ।

विवरण

	श्रेणी	संख्या	सेवा अवधि	वैकल्पिक रोजगार से सम्बन्धित स्थिति
1	कनिष्ठ आशुलिपिक	1	7 वर्ष 3 महीने	रोजगारयुक्त
2	अ० श्रे० लिपिक	6	5 वर्ष 2 महीने	2 रोजगारयुक्त
3	टाईपिस्ट	1	5 वर्ष 2 महीने	रोजगारयुक्त नहीं
4	जी० आपरेटर	1	5 वर्ष 2 महीने	रोजगारयुक्त
5	स्टाफ कार ड्राइवर	1	4 वर्ष	रोजगारयुक्त
6	चपरासी	1	5 वर्ष 2 महीने	रोजगारयुक्त
7	फराश	1	5 वर्ष 2 महीने	रोजगारयुक्त
8	सफाई कर्मचारी	1	5 वर्ष 2 महीने	रोजगारयुक्त नहीं
9	चौकीदार	3	4 वर्ष	रोजगारयुक्त
		16		10 व्यक्तियों ने अब तक वैकल्पिक रोजगार प्राप्त कर लिए हैं ।

उन्हें उनकी उपयुक्तता के आधार पर नए भर्तीशुदाओं के रूप में दूसरे संगठनों में रोजगार मिल गया है । उनकी वरिष्ठता का प्रश्न नहीं उठता ।